मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 15**

05.12.2013 को उत्तर के लिए

**पर्वतीय राज्यों को बांज और उतीस पेड़ लगाने हेतु विशेष आर्थिक सहायता/अनुदान दिया जाना**

**15 . श्री महेन्द्र सिंह माहरा :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तराखंड राज्य सहित देश के सभी पर्वतीय राज्यों में पाये जाने वाले बांज व उतीस के वृक्षों से पानी का स्राव होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी भी है कि इन्हीं पेड़ों के कारण पर्वतीय राज्यों की आधी आबादी को पेयजल सुलभ हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पर्वतीय राज्यों में बांज व उतीस के वृक्ष लगाने हेतु राज्यों व गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता/अनुदान प्रदान करने हेतु विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार पर्वतीय राज्यों में बांज व उतीस के वनों के विकास एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक प्राधिकरण स्थापित करने के संबंध में विचार करेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

(क) और (ख) सामान्यतया वन, जल संरक्षण में सहायक होते हैं और जलभृत का पुनर्भरण जल उपलब्धता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है । विशेष रूप से अध्ययनों से जल स्रोतों के जल पुनर्भरण और बांज के वनों के बीच सकारात्मक सह-संबंध का पता चला है । देश के पर्वतीय राज्यों में आबादी की अधिकांश प्रतिशतता फव्वारों, नदी, धाराओं आदि जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों पर निर्भर हैं ।

(ग) और (घ) सरकार के पास पर्वतीय राज्यों में बांज व उतीस के वृक्ष लगाने हेतु राज्यों व गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष आर्थिक सहायता/अनुदान प्रदान करने की कोई स्कीम नहीं है । तथापि, विविध स्कीमें, जैसे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, एकीकृत जलसंभरण प्रबंधन कार्यक्रम, 13वें वित्त आयोग पंचाट, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण, विभिन्न राज्य योजना/गैर-योजना स्कीमें, बाह्या सहायता प्राप्त परियोजनाओं जिनके तहत, अनाच्छदित अवक्रमित और अनुपजाऊ भूमि पर वनीकरण हेतु सहायता दी जाती है में स्थानीय प्रजातियों को वरीयता प्रदान की जाती है । सरकार के पास पर्वतीय राज्यों में बांज व उतीस के वनों के विकास एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

\*\*\*\*\*\*\*